उमा ने नमामि गंगे में मांगा गायत्री परिवार का सहयोग



हरिद्वार . केंद्रीय मंत्री उमा भारती रिववार देर शाम शांतिकुंज पहुंचीं और गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. प्रणव पण्ड्या और संस्था की अधिष्ठात्री शैल दीदी से लगभग आधा घंटा नमामि गंगे सहित विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा की और सहयोग मांगा।

इस अवसर पर डॉ. पण्ड्या ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे निर्मल गंगा जन अभियान के कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों से उमा भारती को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गंगा शुद्धि, उसकी अविरलता और उसे प्रदूषण मुक्त रखने हेतु तटीय स्थानों में जनजागरण का कार्यक्रम निरन्तर चल रहा है।

पण्ड्या ने कहा, 'मां गंगा को हरी चुनर चढ़ाकर उन्हें प्रदूषण मुक्त करने का अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। गंगोत्री से गंगासागर तक को पांच अंचलों में बांटकर कार्य किया जा रहा है। अभी तक इस अभियान के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण के अंतर्गत गंगा के तटीय स्थानों के दोनों छोरों पर 500 साइकिल टोलियां निकाली जा रही हैं, जो पांचों अंचलों में कार्य करेंगी।'

उमा ने कहा, 'नमामि गंगे भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अभियान है। यह अभियान गायत्री परिवार के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. प्रणव पण्ड्या एवं श्रद्धेया शैल दीदी से मार्गदर्शन एवं आशीष लेने आई हूं। डॉ. पण्ड्या के नेतृत्व में गायत्री परिवार के लाखों कार्यकर्ता जिस तरह से गंगा की निर्मलता व अविस्लता के कार्य कर रहे हैं, उससे एक निश्चित सफलता की किरण दिखाई दे रही है।'

उन्होंने कहा कि सरकार का काम सीमित होता है, जबिक गायत्री परिवार का कार्य असीमित है। उन्होंने अभियान की सफलता के लिए गायत्री परिवार से सहयोग और आशीष मांगा। इस अवसर पर संस्था की अधिष्ठात्री शैलदीदी ने केन्द्रीय मंत्री को उपवस्त्र भेंट कर और मंगल तिलक कर शुभकामनाएं दी।

पाली में सीईटीपी के लिए केन्द्र ने सैद्धांतिक मंजूरी दी

नई दिल्ली @ पत्रिका ब्यूरो. वस्त्र उद्योग इकाइयों के प्रदूषित पानी से अब पाली को निजात मिल सकती है। वस्त्र मंत्रालय ने पाली में कॉमन एफ्युलेन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) निर्माण के लिए अपने हिस्से की 50 प्रतिशत राशि जारी करने की सैद्धोंतिक सहमति दे दी है। पाली

सांसद पीपी चौधरी ने बताया कि अपने हिस्से की 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार मौजूदा बजट में आवंटित कर चुकी है। औद्योगिक इकाइयों की सहभागिता वाले पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, परिशोधन एवं अनुसंधान फाउंडेशन ने भी हिस्से की 25 प्रतिशत राशि जारी कर दी है। 10/13/2015 , :DigitalEdition

नहर टूटी, पांच सौ बीघा खेत जलमग्न

लाखेरी . देहीखेड़ा (बूंदी) @ पत्रिका

patrika.com/city चम्बल सिंचित क्षेत्र की केशवरायपाटन बांच की मुख्य नहर रिववार रात को झपायता के समीप टूट गई। इससे करीब 500 बीधा खेत जलमग्न हो गए। रिववार को अपराह्र करीब तीन बजे टेल क्षेत्र के झपायता नाले के पास नहर में जलप्रवाह शुरू किया था, नाले से आधे किमी दूर ही नहर की बाई तरफ की दीवार में पानी का रिसाव शुरू हो गया। News item/letter/article/editorial published or OCH610-13.10 20/fin the

Hindustan Times Statesman The Times of India (N.D.) Indian Express Tribune Hindustan (Hindi)

Nav Bharat Times (Hindi) Puniab Keshari (Hindi) The Hindu Rajasthan Patrika (Hindi) Deccan Chronicle Deccan Herald

M.P.Chronicle Aai (Hindi) Indian Nation Nai Duniya (Hindi) The Times of India (A) ---Blitz

and documented at Bhagirath(English) & Publicity Section, CWC.

गोमुख से हरिद्वार तक की कार्य योजना पर 19 को बैठक बुलाई

गगा सफाई पर एनजीटी केंद्र और राज्यों से खफा

सरद्रत

नर्ड दिल्ली | विशेष संवाददाता

गंगा के अब तक स्वच्छ और निर्मल नहीं होने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने केंद्र और राज्यों के एक-दूसरे पर जिम्मेदारी मढ़ने की प्रवृत्ति को जिम्मेदार ठहराया है। एनजीटी ने गंगा कार्य योजना का पहला चरण लागु करने के लिए अगले सप्ताह एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। यह एक संघीय ढांचा है, जबावदेही तय करनी होगी : एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंतर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ

केंद्र-राज्य के अफसरों के साथ बैठक 19 को :

एनजीटी ने पर्यावरण एवं मंत्रालय के सचिव या अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय के सचिव, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों, दोनों राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिवों तथा अन्य अधिकारियों को 19 अक्तूबर को बैठक के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। गंगा की सफाई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उस दिन चर्चा होगी, क्योंकि इसने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एमसी मेहता को भी बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया है।

ने कहा कि चर्चा के बाद हमने तय किया कि गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करें, क्योंकि आज तक न्यायाधिकरण की ओर से जारी किए गए तमाम आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ है।

पीठ ने लंबे समय तक इस मुद्दे पर जिम्मेदारी एक-दूसरे पर मढ़ने के लिए केंद्र और राज्यों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, यह एक संघीय ढांचा है। हमें इस पर गौर करना होगा और उसके मताबिक जवाबदेही तय करनी होगी।

नाक 13. 3 के बेव (15 को निम्निसियत समाचार पत्र में प्रकाशित मानसून/ बाढ़ सम्बन्धी समाचार

Hindustan Times (Delhi) ਮੁਕਰਮਾਵਰ ਟਾਊਰਵਾ (ਕਿਲਾਂਸ) The Tribune (Chandigarh) The Hindu (Chennai) The Assam Tribune (Guwahati) The Times of India (Mumbai) The Telegraph (Kolkata) ਡਿਕ੍ਵਪੁਗਰ (ਪਟਗ) The Deccan Hearld (Bengluru)
The Deccan Chronical (Hyderabad)
Central Chronical (Bhopal)

केदारनाथ में मौसम की पहली बर्फबारी

■ प्रस, देहरादून : उत्तराखंड में मौसम के अचानक बदले मिजाज से सर्दी की शुरुआत हो गई है। केदारनाथ में सोमवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई जिसके बाद केदारनाथ क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया। हालांकि कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए आना जारी है। सोमवार को 419 श्रद्धालुओं ने कड़ाके की ठंड में बाबा केदार के दर्शन किए। उ राजधानी देहरादून समेत पहाड़ी इलाकों में सोमवार दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम में ठंडक आ गई।

RELIEF FROM THE SCORCHING HEAT



Heavy rain lashed several parts of the city on Sunday. Three people were electrocuted in Thane district

▶Full Story, P 4

THEMOMHINDU

NATIONAL » OTHER STATES

Published: October 13, 2015 00:00 IST | Updated: October 13, 2015 05:45 IST NEW DELHI, October 13, 2015

Centre, States continue to bicker over cleaning Ganga

· Akanksha Jain



Filthy ghats on the banks of the Ganga in Varanasi.— File Photo

The Centre and the States are engaged in a blame game over cleaning the Ganga yet again, much to the displeasure of the National Green Tribunal (NGT), which on Monday took it upon itself to fix responsibility on the agencies concerned.

Hearing a matter related to the cleaning of the river, the Ministry of Water Resources, Ministry of Environment & Forests (MoEF) and the State of Uttarakhand failed to offer complete answers to issues the tribunal raised.

The NGT Bench, headed by chairperson Justice Swatanter Kumar, was displeased with both the Centre and States concerned passing the buck and remarked, "It is a federal structure. Does the Centre owe responsibility to clear everything or the State should also share the responsibility? We have to look into this aspect and fix accountability accordingly."

"After deliberation it is clear that we should hold a meeting of the following officers, for Section One of Phase-1 of cleaning of the Ganga, at the earliest as various directions passed by the tribunal have not been carried out in true spirit and substance," it added.

"We would expect all the learned counsel (for the Centre, states and the agencies concerned) to lead their part completely and comprehensively, which is at present found wanting," the tribunal remarked while calling an in-chamber meeting of the Secretary (MoEF), Ministry of Water Resources, Chief Secretaries of Uttar Pradesh and Uttarakhand, one representative of the Industries and Principal Secretary (Environment) of both states on October 19. During the hearing, the counsel for the government said the Centre had approved in principal Rs.328 crore to Uttarakhand since 2008, but only Rs.78 crore had been spent.

Advocate General of Uttarakhand said a total of 1,083 establishments, including 396 hotels and 436 ashrams, were operating in Haridwar without environmental clearances. He added that these would be shut down if they did not obtain necessary clearances.

The Centre, meanwhile, had said that almost Rs.4,000 crore has been spent on the rejuvenation of the river since 1985 till last year. It said that the Ganga Action Plan (GAP) Phase-I was launched as a centrally-funded scheme in 1985. Later, GAP Phase-II was initiated in 1993 to improve the river's water quality.

In 2009, the 'National Ganga River Basin Authority' (NGRBA) was set up to control pollution in the river. NGRBA, a World Bank-funded scheme, was aimed at effective abatement of pollution and conservation of the Ganga. As much as 70 per cent of the total project cost was contributed by the Centre, while the remaining was borne by the States.

 $Printable\ version\ |\ Oct\ 13,\ 2015\ 3:41:13\ PM\ |\ http://www.thehindu.com/news/national/other-states/centre-states-continue-to-bicker-over-cleaning-ganga/article 7754994.ece$

© The Hindu

Sunday showers play spoilsport in City

BENGALURU, DHNS: Sudden showers on Sunday afternoon played spoilsport to many Bengalureans, who had stepped out of their homes in the wake of power cuts.

Most parts of Bengaluru west, north and east experienced power cutsdue to maintenance works taken up by Bescom. Many decided to spend the day out, but were stranded in the rain. People were seen running for shelter and roads in the Central Business District saw bumper-to-bumper traffic.

According to the Indian Meteorological Department (IMD) officials, by 5.30 pm the City recorded 7.8 mm rainfall, while HAL and Kempegowda International Airport recorded no rainfall. They also forecast thundershowers in the City and

most parts of South Interior Kamataka over the next two days. The rain caused a drop in temperatures. The City recorded a maximum temperature of 29.4 degree Celsius and aminimum of 21.3 degree Celsius. From October 1 to 11, the City has received 33 mm rainfall, HAL Airport 98 mm and KIAL 62 mm.

The Bruhat Bangalore Mahanagara Palike (BBMP) control room received complaints of fallen tree branches in Chamarajpet, Ashoka Pillar at Jayanagar and near Mysuru Road flyover. Houses in Padarayanapura and Upparpet were flooded. While residents complained of sewage flow on Vittal Mallya Road, waterlogging was reported at St Marks Road. The downpour also affected TenderSure works on Residency Road.



ON A RAINY DAY People try to make their way on the flooded roads in Vittal Mallya Road, after rains lashed the City on Sunday. DH PHOTO

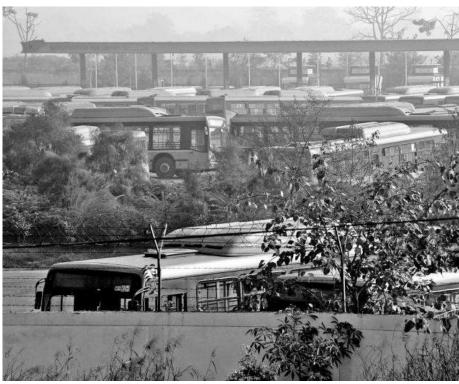
THEMOMHINDU

NATIONAL » OTHER STATES

Published: October 13, 2015 00:00 IST | Updated: October 13, 2015 05:45 IST NEW DELHI, October 13, 2015

HC reserves order on millennium bus depot

• Mohammed Igbal



The High Court had in 2012 directed the DTC to relocate the depot or get the Master Plan Delhi 2021 amended to continue the operations of the millennium bus depot. —file photo

The Delhi High Court on Monday reserved its order on an application of the Delhi Transport Corporation (DTC) seeking to retain the millennium bus depot on the Yamuna riverside.

The plea has sought six months' time to approach the Delhi Development Authority (DDA) for getting the land use of the depot site changed in order to prevent its shifting.

The High Court had in 2012 directed the DTC to relocate the depot or get the Master Plan Delhi 2021 amended to continue the operations of the millennium bus depot, which was constructed during the 2010 Commonwealth Games on the banks of the Yamuna.

Senior advocate Shanti Bhushan, appearing for two environmental activists, on whose writ petition the High Court had passed directions, said the DTC, which had earlier given an undertaking to shift the depot, could not go back on its word now.

The DTC had undertaken before the court in January last year that it would shift the depot to an alternative site provided by the DDA by October 31, 2014. The court later extended the time till August 20 this year.

A Division Bench comprising Chief Justice G. Rohini and Justice Jayant Nath reserved the order on the application after hearing brief arguments.

While the DTC had earlier told the Bench that the issue of changing land use of the depot site was being examined by the Urban Development Ministry, the DDA said that the change was not possible in view of prohibition by the National Green Tribunal on construction in the areas demarcated as zone 'O'.

The DTC has sought six more months to approach the DDA for changing the land use from 'river and water body' to 'transportation'.

Printable version | Oct 13, 2015 3:39:19 PM | http://www.thehindu.com/news/national/other-states/hc-reserves-order-on-millennium-bus-depot/article7755004.ece

© The Hindu

Uttarakhand to initiate processes on stalled hydro-electric projects

Bhadra Sinha

bhadra.sinha@hindustantimes.com

NEW DELHI: The ministry of environment and forest (MoEF), as per a Supreme Court order, can initiate the processing of hydro-electric projects (HEP) for Uttarakhand that are not part of those 24 projects put on hold by the court.

A bench headed by justice Dipak Misra clarified that the apex court's 2013 judgement had banned work of HEPs in the state. It said the court had on August 12, 2014, categorically stated this and asked the MoEF to follow the order.

The court's direction came after an application by the Uttarakhand government, filed through advocate Amit Anand Tiwari, complaining the MoEF's strong stand on the issue had paralysed the state, which was suffering huge financial losses.

The MoEF apparently didn't give permission to examine the sites where companies are expected to install the power plants. "There is no request made for the construction activity," Tiwari later told HT. Also, most of these projects do not even fall in the Alaknanda and

Bhagirathi basin. Fifty-four such projects are awaiting the MoEF's attention.

A bench headed by justice KS Radhakrishnan had in 2013 stayed against clearances to new power projects and ordered the work of 24 HEPs to stop that were already issued environmental and forest clearances.

In the past, the SC had also expressed displeasure over how the environment ministry was dilly-dallying and buying time to undertake a complete assessment of the feasibility of allowing construction of six new hydropower projects.



CITIES » CHENNAI

Published: October 12, 2015 00:00 IST | Updated: October 12, 2015 05:34 IST CHENNAI, October 12, 2015

Overnight rain improves inflow into city reservoirs

• K. Lakshmi

Even though the overnight showers brought down the temperature in the city, making Sunday morning pleasant, pedestrians seemed to have trouble traversing through the waterlogged streets in the city.

However, the rain also brought considerable inflow to the city's major reservoirs, officials said.

Several localities in the southern parts of the city, including Guindy and Meenambakkam, received 2 centimetres of rainfall, while Madhavaram and Nungambakkam received 1 cm, in the 24 hours ending 8.30 a.m. on Sunday.

Puddles of stagnant water near bus stops and railway stations posed a major hurdle for pedestrians across the city. They said the measures taken for monsoon preparedness had little impact as water was unable to enter the storm water drains along the several stretches.

Workers, engaged by Chennai Corporation, had to remove obstructions with their hands, to allow water to flow into the drains.

Those walking on Gandhi Irwin Road were irked over the sewage overflow outside public toilets near Egmore railway station.

Overnight showers resulted in water logging on many arterial stretches, leading to a slowdown in traffic.

Officials of the meteorological department said rainfall over the city was following hot and humid days. A depression over the Arabian Sea also has an influence over the State, officials said. This October has been favourable as Chennai received 7 cm of rainfall, which is excess by 1 cm for this month.

Similarly, Meenambakkam has also recorded 6 cm of rainfall since October 1.

This weather pattern of clear sky and evening showers will continue till Tuesday. "The South West monsoon is still active over some parts. We are expecting the monsoon to withdraw after October 15," said an official.

Normally, North East monsoon, which contributes a major share of rainfall to city, sets in around October 20.

 $Printable\ version\ |\ Oct\ 13,\ 2015\ 3:36:34\ PM\ |\ http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/overnight-rain-improves-inflow-into-city-reservoirs/article \ 7751574.ece$

© The Hindu

The Times of India

Title: Heavy rain lashes city, 3 electrocuted in Thane dist

Author: Location: Mumbai:

Article Date : 10/12/2015

Heavy rain lashed several parts of the city on Sunday evening. There were continuous showers in areas like Ghatkopar and Kurla in the suburbs and Dadar and Matunga in the island city. In the western suburbs, areas like Andheri received rainfall. Kalyan and Thane also witnessed heavy rain.

The rainfall recorded on Sunday between 8.30am-8.30pm by IMD Colaba observatory was 0.2mm and Santacruz was 2.6mm.

Three people were electrocuted after a live overhead wire fell on them at Chande village in Shahapur taluka of Thane district. The victims were identified as Kanhibai Dhupari (45), her son Manoj (5) and Namdev Gangad (35). Police have registered an accidental death report.

At the MMRDA grounds in BKC where Prime Minister Narendra Modi's event was held, some journalists who had come to cover the event were stranded for a few minutes. Several took shelter under a tarpaulin sheet, which also flew off due to gusty winds, which accompanied the rains.

Ghatkopar resident Pravin Shah said, "While we expect the October heat to cause discomfort, these showers are welcome."

The IMD Mumbai on Friday night had forecast that light rain or thundershowers may occur over the weekend. This was on account of a depression over east central Arabian Sea moving northwards. "On Sunday morning, the deep depression over east-central Arabian Sea weakened into a depression at 8.30am. This caused rains in Mumbai," said a weather official.















सरकार २२-२५ अक्तूबर तक खेल कराएगी, वजीराबाद बैराज के पास केंद्र बनेगा

यमुना में वाटर स्पोर्स होंगे

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता

यमुना नदी से दिल्ली वालों को जोड़ने के लिए 22 से 25 अक्तूबर से यमुना के किनारे राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होगी। खेलों से यमुना के किनारे विकसित होंगे और लोग यहां मौज-मस्ती करने आएंगे। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा पहले ही यमुना को एक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किए जाने का ऐलान कर चुके हैं।

सोमवार को अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद सरकार ने तय कर लिया है कि अक्तूबर के आखिरी सप्ताह से पहले इस अस्थायी केंद्र को विकसित कर दिया जाएगा। योजना के तहत यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए अस्थायी शेड और नाव व अन्य उपकरणों को रखने की जगह बनाई जाएंगी। इसके लिए करीब 1 किलोमीटर का क्षेत्र विकसित किया जाएगा। वजीराबाद बैराज से पहले ही यह केंद्र होगा क्योंकि यहां से पल्ला तक यमुना साफ व स्वच्छ है। इस पानी का प्रयोग दिल्ली वालों के पीने के पानी के लिए होता है।

ये इंतजाम करने होंगे

पहुंचने वाले मार्ग: यमुना बैराज तक जाने के लिए अब तक कोई पक्का मार्ग नहीं है। इस मार्ग को ठीक करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग पहंच सकें।

बिजली: घाटों के दूसरे छोर की तरफ बिजली के इंतजाम हैं। मगर इस पूर्वी दिल्ली की तरफ वाले घाटों पर बिजली नहीं है। यहां पर बिजली कंपनियों से नेटवर्क तैयार करवाया जाएगा। बैरिकेड लगाने होंगे: यमुना नदी के मध्य का हिस्सा अधिक पानी होने की वजह से खतरनाक है। इस क्षेत्र तक लोग नहीं पहुंचे इसके लिए बैरिकेड लगाने होंगे।



यमुना नदी में सोमवार को रोइंग करते कुछ युवा। • हिन्दुस्तान

भविष्य में ये प्रावधान होंगे

इस स्पोर्ट्स मीट के बाद यहां पर ऐसा केंद्र विकसित करने की योजना है। जहां पर लोगों को इन खेलों के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। ये आम जनता के लिए भी खुला होगा। इसके लिए एक निर्धारित फीस तय की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह शुल्क नाममात्र रखा जाएगा ताकि आम आदमी की पहुंच इन खेलों तक आसानी से बनी रह सके।

एक पेंच ये भी है

यमुना किनारे में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं की जा सकती। इस ग्रीन कॉरिडोर में स्थायी निर्माण नहीं हो सकते। इसके लिए अभी प्लान में जो भी गतिविधियां करने की तैयारियां की जा रही है। वे अस्थायी होंगी। इससे यमुना के प्रदूषण को रोका जा सकेगा और गिरते जल स्तर को रोकने में भी मदद मिलेगी।